भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3407

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन की स्थिति

3407. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है और उक्त परियोजनाओं को कितने शहरों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है;

(ख) सरकार विशेषकर महाराष्ट्र के तेजी से विकास कर रहे शहरों में शहरी अवसंरचना संबंधी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार कर रही है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे सकारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत, 100 शहरों ने 1,64,545 करोड़ रु. की कुल 8,063 परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। 04.03.2025 तक, 100 स्मार्ट सिटीज द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 1,50,306 करोड़ की 7,504 परियोजनाएं (अर्थात् कुल परियोजनाओं का 93%) पूरी की जा चुकी हैं।

स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 100 शहरों के लिए केंद्र सरकार का कुल परिव्यय 48,000 करोड़ रु. है। 04.03.2025 तक, शहर उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि के उपयोग के अनुसार 47,538 करोड़ रु. (अर्थात् कुल केंद्रीय हिस्से के आवंटन का 99%) की केंद्रीय वित्तीय सहायता का दावा करने में सक्षम हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया है कि उन्होंने 45,772 करोड़ रु. (अर्थात् कुल केंद्रीय हिस्से का 96%) का उपयोग कर लिया है।

(ख) और (ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसके अलावा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243डब्ल्यू) के अनुसार, शहरी नियोजन जिसमें नगर नियोजन भी

शामिल है, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के इन प्रयासों में सहायता करती है।

देश में योजनाबद्ध और व्यापक शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। सभी 4,915 सांविधिक कस्बों और शहरों में स्वच्छता, सभी के लिए आवास और स्वच्छ पेयजल की समस्याओं को राष्ट्रीय शहरी मिशनों जैसे कि स्वच्छता और सफाई के लिए "स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)", सभी के लिए आवास के लिए "प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)", "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" और "अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)" के द्वारा हल किया जा रहा है। इसके बाद, बेहतर और तेज़ शहरी प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एससीएम के तहत 100 शहरों का चयन किया गया है। इसके अलावा, शहरी मोबिलिटी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) भी चालू है।

*****